

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोक

(चिन्मयी गोपाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 33/2021
प्रविष्टि दिनांक 24.03.2021
बजरंगा पुत्र नानगा जाति गीणा निवासी लसाडिया तहसील उनियारा जिला टोक राज०
—अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार उनियारा जिला—टोक

—रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
तहसीलदार उनियारा दिनांक 12.01.2021 मिसल नम्बर 75/2020

उपरिस्थिति : (1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री रामप्रसाद कुमावत, नायब तहसीलदार राजकीय परोकार

निर्णय

दिनांक 23.05.2022

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने निर्णय दिनांक 12.01.2021 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 388 रकबा 0.35 है० किरम चरागाह वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर मकान व मसूर की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से वेदखल करने, 140/रु. पेनल्टी कायम कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेंट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की वहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों का दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सवृत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई ओर न मौके का निरीक्षण किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर से वर्तमान में अपना कब्जा हटा लिया है। पटवारी हल्का द्वारा दुर्भावनापूर्वक अपीलान्ट के विरुद्ध रिपोर्ट पेश की है। अपीलान्ट ने कब्जा छोड़ने बाबत शपथ पत्र अपीलान्ट के



जिला कलेक्टर
टोक

साथ ही प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 388 रकबा 0.35 है, किस्म चरागाह वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान एवं मसूर की फसल काश्त करने पर तहसीलदार उनियारा द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम कर 3 माह की सिविल कारावास की दजा से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है, परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की ओर से उसकी पत्नि की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 388 रकबा 0.35 है, किस्म चरागाह वाके ग्राम लसाडिया तहसील उनियारा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर मकान बनाकर एवं मसूर की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से सिद्ध है। अपीलान्ट द्वारा दिनांक 18.03.2021 को न्यायालय हाजा में अपील मीमो के साथ ही शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त आराजी पर से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है। भविष्य में उपरोक्त भूमि अथवा किसी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में मकान का उल्लेख नहीं है। पत्रवली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहते है और राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने के आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पीपलू का निर्णय दिनांक 12.01.2021 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



दिनांक
जिला कलेक्टर
जिला कलेक्टर, टोक